आकाशवाणी शिमला

मुख्य समाचार

- राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी– वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के सभी संप्रदायों और महिलाओं का होगा प्रतिनिधित्व।
- केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रीय हित में बताया।
- केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए दो सौ 67 करोड़ रूपए किए स्वीकृत।
- तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा–लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध।

राज्यसभा–वक्फ

राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। विधेयक को पेश करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक को हितधारकों के साथ–साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वक्फ का लाभ सिर्फ मुस्लिमों को ही मिल सकता है और यह सही नहीं है कि कोई गैर–मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है, न कि मुसलमानों के धार्मिक व्यवहार में हस्तक्षेप करना। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के सभी विभिन्न संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा ताकि इसे समावेशी बनाया जा सके।

जगत प्रकाश नड्डा

इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस बिल के संशोधन में पूरे नियमों का पालन किया गया है। उन्होनें कहा कि मुझे आशा है कि उम्मीद यानि एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास का समर्थन होगा। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का किसी भी तरह से कोई दुरुपयोग न हो, इसलिए ये बिल आज के समय के लिए आवश्यक है। नड्डा ने कहा कि पिछले 70 सालों तक वोट बैंक के लालच में एक वर्ग को डराकर रखा गया। मुस्लिम समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि ये बिल राष्ट्र हित में है।

सिकंदर कुमार

राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और गरीब मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम महिलाओं व पिछड़े मुस्लिम समाज को इसमें हिस्सेदारी व न्याय मिलेगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार अब ये सुनिश्चित करेगी कि वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा कैग के माध्यम से होगा और संपत्तियों का सुनियोजित प्रबंधन इस समाज के हित में होगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड को किसी

भी संपत्ति को वक्फ की घोषित करने का कोई अधिकार नहीं होगा और सरकारी संपत्तियों पर भी वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अधीन संपत्तियों का उपयोग अब केवल सामाजिक कार्यों में होगा।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारतीय सेना देश की शान हैं और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सेना का अहम योगदान है। लोकसभा में आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन से चीनी अधिकारियों से पैसा क्यों लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा विदेशी ताकतों के साथ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना का मनोबल बढ़ाया है और कोई भी भारत की एक इंच तक जमीन नहीं ले पाया। उन्होंने कहा कि डोकलाम की घटना के समय भारत की सेना ने चीन को मुहंतोड़ जवाब दिया था।

विक्रमादित्य सिंह

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए दो सौ 67 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025–26 में पूंजी परिव्यय के तहत केंद्र सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 14 सौ करोड़ रूपए की मांग की गई है, जिसमें से पहले चरण में दो सौ 67 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने ये राशि जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी का आभार जताया है। लोकनिर्माण मंत्री ने बताया कि जलोड़ी जोत टनल का एलाइनमेंट कार्य पूरा किया जा चुका है और अब इसकी एक हजार 4 सौ 52 करोड़ रूपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रणौत पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि 11 महीने की देरी के बाद मंडी में दिशा प्रो–डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया है और सांसद के अधीन होने वाली दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने का भी कंगना रणौत के पास समय नहीं है।

धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिलासपुर में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने की आवश्यकता है। राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने और इन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने और सिंचाई सुविधा प्रदान करने को भी कहा। राजेश धर्माणी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि जिले में सिंथेटिक ड्रग्स के खतरे पर विशेष ध्यान दिया जाए और पंचायत स्तर पर ड्रग्स की स्थिति की मैपिंग की जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख भी किया।

कुलदीप सिंह पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में बीते दो वर्षों के दौरान 40 सड़कों का कार्य शुरू किया गया हैं जिनमें से लगभग 22 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने आज क्षेत्र की ढलोग व बगढ़ार पंचायत में दो संपर्क सड़कों का भूमि पूजन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही क्षेत्र के शेष लगभग एक सौ 25 गांवों को भी संपर्क सड़क सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के बजट में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए सौ करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

चंद्र कुमार

कृषि व पशु पालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठा रही है। वे आज ज्वाली में सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। चंद्र कुमार ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की लगातार घटती संख्या पर चिंता जताते हुए अध्यापकों से शिक्षा की गुणवत्ता और नामाकंन बढ़ाने का आह्वान किया। बाद में उन्होंने उपमंडल के विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर भी एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी– वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के सभी संप्रदायों और महिलाओं को होगा प्रतिनिधित्व।
- केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रीय हित में बताया।
- केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए दो सौ 67 करोड़ रूपए किए स्वीकृत।
- तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा–लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध।